

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 65  
दिनांक 21जून, 2019 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

65. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि:

- (क) 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना' योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;  
(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;  
(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं; और  
(घ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को उक्त योजना के तहत लाभ से वंचित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 01 जनवरी, 2017 से केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) चला रहा है । अब तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना -सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई - सीएस) पर पूरे देश से 95,56,577 लाभार्थियों से 2,28,09,417 आवेदन प्राप्त हुए हैं (18 जून, 2019 तक की स्थिति के अनुसार) । 82,18,494 पात्र लाभार्थियों को 31,47,80,49,000 रुपये (केंद्रीय एवं राज्य शेयर सहित) के मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया है ।

(ख) और (ग) : पीएमएमवीवाई के तहत संस्वीकृत/निर्मुक्त तथा लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में संलग्न है ।

(घ) : पीएमएमवीवाई के तहत पात्र महिलाओं को लाभ प्रदान न किए जाने का ऐसा कोई मामला मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है ।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक**

**प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा दिनांक 21.06.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 65 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित विवरण**

**प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्वीकृत/निर्मुक्त निधियों और लाभार्थियों की संख्या  
दर्शाने वाला विवरण (18.06.2019 को)**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत/निर्मुक्त निधि का केंद्रीय शेयर (रुपये लाख में)	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	249.96	3,317
2.	आंध्र प्रदेश	21,124.11	6,02,242
3.	अरुणाचल प्रदेश	948.83	6,608
4.	असम	11,265.26	1,89,085
5.	बिहार	18,604.38	3,76,489
6.	चंडीगढ़	594.82	11,615
7.	छत्तीसगढ़	6,408.43	2,15,811
8.	दादर और नागर हवेली	178.47	3,677
9.	दमन और दीव	90.54	1,864
10.	दिल्ली	2,804.65	90,465
11.	गोवा	276.11	9,002
12.	गुजरात	16,145.84	4,08,490
13.	हरियाणा	7,999.14	2,63,428
14.	हिमाचल प्रदेश	3,945.22	92,301
15.	जम्मू और कश्मीर	3,966.26	82,386
16.	झारखंड	7,076.07	2,05,931
17.	कर्नाटक	16,824.73	4,85,170
18.	केरल	9,050.91	2,75,080
19.	लक्षद्वीप	32.26	483
20.	मध्य प्रदेश	30,902.00	10,83,029
21.	महाराष्ट्र	24,616.72	7,54,131
22.	मणिपुर	1,549.07	11,556
23.	मेघालय	1,212.83	6,438
24.	मिजोरम	1,005.48	12,145
25.	नागालैंड	1,087.06	4,875
26.	ओडिशा*	7,526.33	5
27.	पुदुचेरी	395.21	9,280
28.	पंजाब	6,678.57	1,80,792
29.	राजस्थान	21,092.40	7,00,944
30.	सिक्किम	375.33	4,408
31.	तमिलनाडु	12,745.85	2,18,173
32.	तेलंगाना**	7,581.40	0
33.	त्रिपुरा	1,941.49	28,234
34.	उत्तर प्रदेश	48,263.40	14,73,639
35.	उत्तराखंड	4036.65	72,110
36.	पश्चिम बंगाल	13,183.75	3,35,291
	<b>कुल योग</b>	<b>3,11,779.52</b>	<b>82,18,494</b>

\* राज्य अपना मातृत्व लाभ कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। मंत्रालय राज्य को अपने मातृत्व लाभ कार्यक्रम के साथ को-ब्रांडिंग के तहत पीएमएमवीवाई को क्रियान्वित करने की अनुमति देता है।

\*\* राज्य अपना मातृत्व लाभ कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। मंत्रालय राज्य को अपने मातृत्व लाभ कार्यक्रम के साथ को-ब्रांडिंग के तहत पीएमएमवीवाई को क्रियान्वित करने की अनुमति देता है। तकनीकी एकीकरण का परीक्षण कर लिया गया है।